लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16 - 31 मार्च 2023   www.haryanasamvad.gov.in   अंक - 62

"किसी भी राष्ट्र का परिचय उसके अनुशासनबद्ध नागरिकों से मिल जाता है।"
: महात्मा गांधी

भ्रष्टाचार पर मंथन 2

कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन से मिलेगा फायदा 4

म्हारा देस म्हारी संस्कृति 8

बढ़ रही पेंशन, मिल रहा सम्मान

G20 भारत 2023 INDIA

विशेष प्रतिनिधि

बुढ़ापे में मिलने वाला जेब खर्च अमूल्य होता है। बुजुर्ग माता-पिता इसे 'रात का गहना' मानते हुए बहुत संभाल कर रखते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जितना सहारा लाठी का होता है सच मानिये उतना ही सहारा इस जेब खर्ची का होता है। घर परिवार में बाल बच्चे न हों तो यह मामूली राशि और बड़ी हो जाती है। रसोई खर्च के अलावा कभी दवा की जरुरत तो कभी किसी फल की इच्छा, ऐसे वक्त में यह मामूली भत्ता बड़ा सहारा होता है। दिल मसोसकर नहीं रहना पड़ता, आत्मसम्मान की अनुभूति होती है।

हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की शुरुआत 100 रुपए मासिक की राशि से हुई थी। वर्ष 2014 में यह राशि एक हजार रुपए थी, मनोहर सरकार बनने पर यह राशि 2500 रुपए हो गई । आगामी एक अप्रैल, 2023 से यह मासिक पेंशन 2,750 रुपए मिलने लगेगी।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में साढ़े 18 लाख बुजुर्गों को लगभग 460 करोड़ रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय की पात्रता सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। भविष्य में जो व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा तथा पति-पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी, उनकी पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगी। उनसे केवल पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'सीधा संवाद' की शृंखला में सम्मान भत्ता के नये लाभार्थियों से संवाद किया तो लाभार्थी अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवार, मेरा परिवार हैं, जिनके प्रत्येक सदस्य की चिंता राज्य सरकार कर रही है। सरकार पीपीपी के साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ रही है ताकि पात्र व्यक्ति को घर बैठे उनका लाभ मिले और कोई अपात्र व्यक्ति लाभ न ले पाये।

गौरतलब है कि बुढ़ापा पेंशन स्कीम, पहली योजना है, जिसे सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा है। विगत 6 माह के दौरान लगभग 16,500 बुजुर्गों की पेंशन स्वतः बनी है। वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े ।

अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए योजना: वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के सवा दो लाख बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग ऐसे हैं, जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी या वॉलंटीयर्स महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, सम्पत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी, तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी।

समाजसेवा के लिए आगे आएं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मान भत्ता लाभार्थियों से आह्वान किया कि 60 वर्ष की आयु के बाद वे समाज सेवा के लिए आगे आएं। सरकार ने 'समर्पण' पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वालंटीयर के तौर पर स्वयं का पंजीकरण करवा सकता है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारी संस्कृति है, इसलिए सभी को समाज की चिंता भी करनी चाहिए।

योजनाओं को जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अप्रैल, 2023 से ही नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का बारीकि से अध्ययन करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, एक अप्रैल से किराए में 50 प्रतिशत छूट के साथ यात्रा कर सकेंगे।

बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत इस वर्ष 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। म्हारा गांव - जगमग गांव योजना के तहत 5694 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शेष गांवों को भी जल्द इस योजना के तहत लाया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सड़कों की मरम्मत, चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दें। युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है, पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अभिनेता सतीश कौशिक का निर्वाण

हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता एवं निर्देशक सतीश कौशिक नहीं रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतीश कौशिक के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया और कहा कि बेमिसाल अभिनय और निर्देशन के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा।

सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में हुआ था। वे हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक भी थे। फिल्म जगत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए राज्य सरकार ने हरियाणवी फिल्मों के माध्यम से प्रादेशिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त था।

कौशिक ने चैयरमैन रहते हुए हरियाणवी फिल्मों को निरंतर बढ़ावा दिया। हरियाणवी संस्कृति को प्रोत्साहन में उनका योगदान सदैव प्रशंशीय रहेगा।

भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश का संकल्प

सरकारी कामकाज में हेराफेरी करने वालों पर सख्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश व प्रदेश के सरकारी कामकाज में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। विकास कार्यों के दृष्टिगत अवांछित परंपराओं को या तो बंद किया गया है या उनमें सुधार किया गया है। उल्लेखनीय है कि सबका साथ, सबका विकास की नीति पर खरा उतरने के लिए कामकाज में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है ताकि सबका विश्वास जुड़ सके ।

डिज़िटलाइजेशन के चलते अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के कामकाज में नाहक हस्तक्षेप लगभग बंद हो गया है संबंधित व्यक्तियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है तथा बिचौलिया राज खत्म हुआ है। कार्यालयों में न केवल सरकारी बाबूओं के काम करने का ढंग बदला है, निकायों के मुखिया, विधायक एवं सांसदों की कार्यशैली में भी सकारात्मक बदलाव हुआ है।

प्रदेश से जातिवाद, क्षेत्रवाद व भाई-भतीजावाद को समाप्त करके प्रत्येक वर्ग के कल्याणार्थ अनेकों योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए एक लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपए का बजट रखा है जिसमें समग्र विकास की रूपरेखा है।

मनोहरलाल ने वर्ष 2014 में प्रदेश के मुखिया की कुर्सी संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि वे सुशासन के लिए कुछ भी करेंगे। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तथा भेदभाव समाप्त करने के लिए समस्त सरकारी कामकाज पारदर्शी होगा। अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं होगी, जीरो टोलरेंस पर काम होगा तथा हेराफेरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पनपने के तमाम छिद्रों को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास में सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए नई नीति ई टेंडरिंग पर काम हो रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो तथा लोगों को उसका पूरा फायदा मिले। ई-टेंडरिंग लागू होने के बाद पंचायतों में काम तेजी से होंगे तथा जिम्मेदारी तय होगी। इसके साथ ही पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आम जनता व ग्रामीण पोर्टल पर अपने गांव के विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पंचायत को विकास कार्यों के लिए सभी प्रशासनिक शक्तियां प्रदान कर उन्हें और सशक्त किया गया है।

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते पखवाड़े के दौरान 1.66 लाख रुपए से अधिक की रिश्वत लेते एक आईटीआई प्रिंसिपल, दो पुलिस अधिकारी, दो पटवारी, एक ग्राम सचिव और एक ऑक्शन रिकॉर्डर सहित सात आरोपियों को काबू किया। सभी गिरफ्तारियां करनाल, गुरुग्राम, पानीपत, कैथल, सिरसा और भिवानी जिलों से की गई। हाल ही में पानीपत से पब्लिक हैल्थ के दो बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है।

- मनोज प्रभाकर

संपादकीय

शिक्षा में निवेश

शिक्षा समाज की उन्नति और भविष्य को सुरक्षित करने वाला निवेश है जिससे राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन में उजियारा आता है और वह सदैव कांतिमय बनकर चमकता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने शिक्षा में निवेश को बड़ा महत्व दिया है। आगामी वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 20636 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए 1663 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है ताकि युवाओं को कौशल शिक्षा के जरिए रोजगार आसानी से मुहैया हो सकें।

आगामी वर्ष में शिक्षा पर जो निवेश होगा वह केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। नई शिक्षा नीति की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हाल ही में राजभवन में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुलसचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने भी इस बैठक में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय यह संकल्प लें कि नई शिक्षा नीति का समाज के हर नागरिकों को लाभ मिले और इस नीति को लागू करने के लिए बनाए गए प्रत्येक पैरामीटर पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसके साथ ही प्रत्येक चरण में नई शिक्षा नीति की समीक्षा करें और इसके लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के लिए कई विश्वविद्यालयों में केजी टू पीजी तथा इंटीग्रेटेड एजुकेशन के साथ शोध कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि 2025 तक नई शिक्षा को हरियाणा में पूरी तरह से लागू किया जा सके।

नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस सेंटर के रूप में कार्य करना होगा। विश्वविद्यालय रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन करें तथा इसके अलावा तकनीकी पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दें ताकि छात्र शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। विश्वविद्यालयों को पीपीपी मोड में पाठ्यक्रमों का संचालन करना होगा जिससे विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें। राज्य सरकार की ओर से 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को फीस की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

शिक्षण संस्थानों द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा को भी बढ़ावा देना आवश्यक है जिससे युवा वर्ग रोजगार के साथ-साथ सामाजिक जीवन मूल्यों का भी निर्वहन कर सके।

-डा. चंद्र त्रिखा

मुख्यमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बनवाए गए उपहार पोर्टल को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार यह कार्य किया है जो साबित करता है कि मुख्यमंत्री जब यह कहते हैं कि पूरा हरियाणा ही उनका परिवार है तो यह सिर्फ़ एक बयान भर नहीं होता, बल्कि इसमें पूरी सच्चाई निहित होती है। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी से प्राप्त डोनेशन को समाज की भलाई के लिए ही खर्च किया जाएगा। उपहार पोर्टल के जरिए नीलामी के लिए रखे गए कुल 51 उपहारों को एक करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपए का डोनेशन मिला है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व सूचना, जनसम्पर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि मनोहर लाल की थ्री डी प्रिंटेड प्रतिमा की 21 लाख रुपए की बोली लगाई गई है। अर्जुन रथ की आकृति को 6 लाख 41 हजार रुपए, कामाख्या देवालय की आकृति को 5 लाख 80 हजार रुपए और राम जन्म भूमि मंदिर की प्रतिमा को 1 लाख 75 हजार रुपए की बोली लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उपहारों से प्राप्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी और इसे जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप भेंट किए गए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया था। मनोहर लाल की इस पहल के बाद मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया और पहले चरण में 28 फरवरी तक 51 उपहारों की नीलामी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल पर हर उपहार के साथ उसकी बेस राशि अंकित की गई थी। उन्होंने बताया कि पहले चरण की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से बोली दाताओं को उपहार को ससम्मान भेंट करेंगे।

-संवाद ब्यूरो

हाईटेक हुई हरियाणा पुलिस

हरियाणा पुलिस ने आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करते हुए केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित परियोजना इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसे प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने का एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू आईसीजेएस परियोजना को गृह मंत्रालय के ज़रिए पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है जिस पर प्रदेश पुलिस आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।

परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रदेश में लागू किया गया है। हरियाणा पुलिस ने आईसीजेएस परियोजना का उपयोग करते हुए 45 वाहनों को ट्रेस करने में, 67 उद्घोषित अपराधियों व बेल जम्पर्स और 02 मोस्ट वांटेड अपराधियों को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उक्त डेटा पर ही 4 एफआईआर भी प्रदेश में दर्ज़ की गई हैं।

आईसीजेएस के पहले चरण में अलग-अलग आईटी सिस्टम को लागू और व्यवस्थित किया गया है। इन सिस्टम को रिकॉर्ड को सर्च करने में भी सक्षम बनाया गया है। वहीं चरण-2 के तहत इस सिस्टम को 'एक डेटा, एक एंट्री' के सिद्धांत पर तैयार किया गया है, जिसके तहत डेटा केवल एक कॉलम में केवल एक बार दर्ज़ किया जाता है और फिर वही डेटा अन्य सभी कॉलम में दर्ज़ हो जाता है। इसके लिए प्रत्येक कॉलम में डेटा की फिर से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है।

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर जिम्मेदारीः

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निदेशक ओपी सिंह ने बताया कि आईसीजेएस सिस्टम को हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक डेडिकेटिड और सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुख्य आईटी सिस्टम के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जिसका इस्तेमाल पांच कॉलम के ज़रिए देश में आपराधिक न्याय को लागू करने के लिए किया जाता है। पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली), फॉरेंसिक लैब के लिए ई-फॉरेंसिक, न्यायालयों के लिए ई-कोर्ट, लोक अभियोजकों के लिए ई-प्रॉसीक्यूशन, जेलों के लिए ई-जेल। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश पुलिस जेलो में बंद अपराधियों का पूर्ण रिकार्ड रहता है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर में अपराधी का नाम व अन्य सूचना की एंट्री करने से, यदि किसी अन्य राज्य में उसकी स्थिति है तो तभी अपडेट हो जाती है। उक्त सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी आगामी कार्यवाही कर सकते है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक अपराधी कई राज्यों में वांछित होता है और किसी अन्य राज्य में जेल में बंद होता है। ऐसी स्थिति में इस सॉफ्टवेयर पर जो डाटा बेस उपलब्ध है उसकी सहायता से अपराधियों की वर्तमान लोकेशन को ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से चोरी हुए वाहनों का पता लगा सकते हैं।

आईसीजेएस सॉफ्टवेयर पर कार्य करते हुए कुल 14 उद्घोषित अपराधी व बेल जम्पर्स सर्च किए हैं। जो सभी पी.ओ./बेल जम्पर्स जिला रेवाड़ी के विभिन्न थानों मे दर्ज अभियोगो में वांछित चल रहे थे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले ने विभिन्न थानों से चोरी हुई कुल 11 मोटर साइकिलें, हिसार व हांसी ने सात वाहनों व रोहतक ने नौ वाहनों का पता लगाने मे भी सफलता प्राप्त की है।

प्रथम रैंक से सम्मानित होने का गौरवः

गृह मंत्रालय के तहत हरियाणा पुलिस ने आईसीजेएस परियोजना के सर्वश्रेष्ठ ि यान्वयन की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छी प्रथाओं का प्रसार करने के लिए व सीसीटीएनएस और आईसीजेएस परियोजनाओं को बेहतरीन तरीके से लागू करने व राज्यों द्वारा बेहतर प्रणाली के प्रचार-प्रसार के लिए व उनके द्वारा किये जा रहे निरंतर प्रयासों को मान्यता देने के सम्मेलन आयोजित किया गया था।

- संवाद ब्यूरो

कैशलेस चिकित्सा सुविधा का विस्तार

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की गई है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस योजना से बोर्डों और निगमों सहित लगभग 3.35 लाख परिवार (लगभग 14.30 लाख व्यक्ति) कर्मचारी लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, पेंशनधारकों के 3.05 लाख परिवार (6.10 लाख व्यक्ति), मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के 1200 परिवार (लगभग 4800 व्यक्ति), आजाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार (848 व्यक्ति), हिंदी आंदोलन से जुड़े 186 परिवार (372 व्यक्ति), आपातकाल के दौरान जेल में बंद 555 परिवार (1,110 व्यक्ति) और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद 614 परिवार (1228) इस योजना से लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर इस व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 6 लाख 52 हजार परिवारों (20.48 लाख व्यक्ति) को कवर किए जाने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल सीसीएचआईएस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। प्रभजोत सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से इस योजना के संबंध में टिप्पणियां व सुझाव मांगे जा चुके हैं। इनके अलावा, विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों निगम, मिनिस्टिरियल एजुकेशन कर्मचारियों के विभिन्न कर्मचारी और पेंशनधारक यूनियनों के भी सुझाव लिए गए हैं।

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर :	संगीता शर्मा
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

हर ब्लॉक में अधिक आबादी वाले पांच गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने, पीएचसी, स्कूल आदि की मरम्मत व 5 करम के रास्तों को पक्का बनाने का कार्य जिला परिषद करेंगी।

गौशालाओं के बजट में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि गायों के पालन-पोषण में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इस वर्ष बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है।

संगीता शर्मा

भ्रष्टाचार पर मंथन

गुरुग्राम में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान जी-20 के सदस्य, 10 आमंत्रित देशों व 9 अंतराष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतराष्ट्रीय सहयोग पर मंथन किया। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई को मज़बूत करने व आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित संपत्ति वसूली तंत्र को मज़बूत करने व आपराधिक मामलों में घरेलू कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मौजूदा पारस्परिक कानूनी सहायता ढांचे में सुधार और तंत्र को सरल बनाने पर व्यापक विमर्श किया गया।

भ्रष्टाचार और संबंधित आर्थिक अपराधों के खिलाफ़ लड़ाई को मज़बूत करने, संपत्ति की रिकवरी और अंतराष्ट्रीय सहयोग को गति प्रदान करने के लिए भारत पहली एसीडब्ल्यूजी की मंत्रिस्तरीय बैठक की भी मेज़बानी करेगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए एक ऐसा प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की कल्पना की है, जिसमें भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस नीति शामिल हो। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए भारत

> हरियाणा के लिए यह गौरव की बात है कि गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों को भारत की 'अतिथि देवो भव' की परंपरा और समृद्ध कला संस्कृति से रू-ब-रू कराने के लिए मेज़बान प्रदेश की ओर से यह आयोजन किया गया है। बैठक में इस विषय पर हुए वैचारिक आदान-प्रदान लोक प्रशासन को और अधिक मजबूत करने में मद्दगार साबित होंगे।
>
> **- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा**

की जी 20 अध्यक्षता का लक्ष्य भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर व्यावहारिक एक्शन-ओरिएंटिड प्रयासों पर फोकस करना है, ताकि भ्रष्टाचार निरोधी मामलों में अंतराष्ट्रीय सहयोग और भ्रष्ट लोगों तथा भ्रष्टाचार का सामना करने की जी-20 समूह की प्रतिबद्धता को मज़बूत किया जा सके।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कई बार आर्थिक अपराधों का सामना करना पड़ा है और विशेषकर जब अपराधी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस संबंध में एक विशेष कानून भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 बनाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने और मामलों के समय पर निपटान के लिए द्विपक्षीय समन्वय की बजाय बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता है, जो अधिक जटिल साबित होता है और एफईओ से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने तथा संबंधित संपत्तियों की वसूली में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय व बैंकिंग धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच कानूनी प्रावधानों के तहत की गई और इन मामलों में हाई नेटवर्थ वाले लोग शामिल थे, जिनकी अपराध से आय लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।

प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने दी प्रेजेंटेशन

जी-20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप (एसीडब्ल्यूजी) की तीन दिवसीय बैठक के आखिरी दिन डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव एवं जी-20 एसीडब्ल्यूजी भारत के अध्यक्ष राहुल सिंह व सह अध्यक्ष एवं इटली में हेड ऑफ टास्क फोर्स जियोवन्नी टार्टाग्लिया पोलसिनी ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। राहुल सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में तीन दिन तक चली इस बैठक में अंतराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधियों से संपत्ति की रिकवरी, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ़ कार्रवाई के लिए सूचना सांझा करने में सहयोग के चैनल विकसित करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे और आपसी कानूनी सहायता से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों पर गहनता से विचार-विमर्श हुआ है। इस बैठक में यूएनओडीसी, ओईसीडी, एगमोंट ग्रुप, इंटरपोल व आईएमएफ आदि अंतराष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने भी भारत की ओर से इस बैठक में अपना संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि बैठक में विचार-विमर्श के दौरान प्रतिनिधियों का यह प्रयास रहा है कि वे उच्च स्तरीय सिद्धांतों के प्रारूप पर आम सहमति पर पहुंचे, जोकि भारत की अध्यक्षता में जी-20 एसीडब्ल्यूजी के एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल है।

सेल्फी प्वाइंट्स पर प्रदेश की विकास यात्रा

अंतराष्ट्रीय बैठक के आयोजन स्थल के समीप प्रतिनिधियों को हरियाणा की कला एवं संस्कृति तथा सुशासन आधारित कार्यक्रमों से अपडेट कराने के लिए एक स्टाल भी लगाई गई। हरियाणा के खिलाड़ियों, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और राज्य की कला-संस्कृति से मेहमानों को रूबरू कराने के लिए सेल्फी प्वाइंट व डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए। हरियाणवी संस्कृति व स्थानीय पर्यटन केंद्रों की जानकारी के लिए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा द्वारा ब्रोशर तैयार किया है। हरियाणा की स्टाल पर मेहमानों के लिए यह ब्रोशर उपलब्ध रहा। इसी तरह हरियाणा सरकार की उपलब्धियों व प्रदेश के गौरवशाली पहलुओं को प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी मेहमानों को दिखाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम एक धरा-एक परिवार-एक भविष्य के साथ आधारभूत ढांचागत विकास का प्रारूप जी- 20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग में देखने को मिला।

सुल्तानपुर झील के मनोरम दृश्य

विभिन्न देशों के डेलिगेट्स ने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी (रामसर साइट) का दौरा किया। हरियाणा के गुरुग्राम में करीब 350 एकड़ क्षेत्र में फैली सुल्तानपुर बर्ड सेंच्युरी को यूरोप, साइबेरिया व मध्य एशिया के प्रवासी पक्षियों का सर्दियों में प्रमुख केंद्र माना जाता है। विदेशी मेहमानों को सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के भ्रमण के दौरान प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में जी-20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की स्थाई स्मृति बनाए रखने के लिए सभी देशों व संगठनों के प्रतिनिधियों से पौधरोपण भी कराया गया। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह गठित कर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के प्रेरक कार्य से भी डेलिगेट्स भ्रमण के दौरान रूबरू हुए।

पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव डा.एमडी सिन्हा ने रामसर साइट में शामिल सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी व यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों से जुड़ी जानकारी से डेलिगेट्स को अवगत कराया। सर्दियों की शुरुआत से ही यहां पर विदेशी पक्षियों का आगमन शुरु हो जाता है। भारत की इस प्रमुख बर्ड सेंचुरी में हर साल करीब 250 प्रजातियों के लाखों पक्षी यहां पर प्रवास करते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की विशेषताओं को देखते हुए इसे अब रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है।

ग्रामीण महिलाओं को सराहना

जी-20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के डेलिगेट्स ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल का अवलोकन करने के दौरान स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्य महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों में विशेष रुचि दिखाई। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सीईओ डा. अमरिंदर कौर ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं अपने कौशल विकास की वृद्धि कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं।

मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पाद

अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर-मोटा अनाज वर्ष के तहत सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं ने बाजरे के बिस्किट, ज्वार की नमकीन व रागी के चिप्स आदि भी परोसे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मिलेट्स स्टॉल भी लगाई गई थी। उप निदेशक कृषि डा. अनिल तंवर ने डेलिगेट्स को मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, सामक आदि के महत्व व पोषक तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर लगभग 60 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 44 करोड़ और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने इकाइयों से 15 करोड़ रुपए की वसूली की।

अमृतकाल में गांवों में जल संचयन की पुरानी पद्धति जैसे जोहड़ व तालाब आदि को पुनर्जीवित व विकसित करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन से मिलेगा फायदा

कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत खेती में एक नया आयाम स्थापित करेगी। इस तकनीकी के लिए कृषि प्रधान देश कनाडा और कृषि प्रधान राज्य हरियाणा एक-दूसरे के साथ आधुनिकतम तकनीक, मशीनरी को सांझा करेंगे।

पिहोवा वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा कुरुक्षेत्र के गांव तलहेड़ी के एफपीओ पैक हाऊस में आयोजित स्वच्छ बीज उत्तरी किसान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं कनाडा के प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि प्रधान देश कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन का डेमो पिहोवा-कुरुक्षेत्र में दिखाया गया। इस डेमो के बाद इस आधुनिक तकनीक की मशीन को भारत सरकार के माध्यम से खेती के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे किसानों को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। उन्होंने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कनाडा के स्कैचवन राज्य के प्रीमियर स्कॉट मोई और बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सिंह सैनी के साथ एफपीओ पैक हाउस का अवलोकन किया।

गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडीः पेरिस, फ्रांस, हॉलैंड जैसे देशों में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडियों की तर्ज़ पर हरियाणा के गन्नौर में 550 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर अलाट कर दिए जाएंगे। इससे किसानों के उत्पाद विदेशों तक पहुंचेगे तथा किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

आधुनिक तकनीक अपनाएंः कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए पिछले कई वर्षों में मशीनीकरण हुआ है और कृषि के आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं। वर्तमान में ड्रोन स्मार्ट एग्रीकल्चर का ज़माना है, इसी तरह क्लीन सीड कृषि बदलाव की एक बेहतरीन तकनीक है, जोकि वर्तमान में सबसे आगे कार्य कर रही है। यह एक अद्वितीय हाई-डेफिनिशन सीडिंग तकनीकों में से एक मानी जाने वाली तकनीक है, जिससे कृषि में बदलाव लाया जा सके। इस तकनीक के लिए हरियाणा व कनाडा के स्कैचवन राज्य की टीम मिलकर कार्य करेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि कनाडा के कृषि प्रधान राज्य स्कैचवन से एक प्रतिनिधि मंडल का भारत आने का उद्देश्य कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन को भारत में प्रदर्शित करना है। इस मशीन को भारत की कृषि प्रणाली के हिसाब से संशोधित करके भारत में जल्द ही लाया जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

गेहूं, सरसों व कपास के रोग, लक्षण व उपचार

गेहूं

गेहूं की फसल में बंटः यह रोग प्रदेश में नमी वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। इस रोग से दानों में काले रंग का पाऊडर बन जाता है और इससे सड़ी मछली की गंद्य आती हैं। कुछ दानों मे व किन्ही बालियों में इस बीमारी का प्रकोप होता है।

प्रबंधनः-रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें। रोगरोधी किस्मों का रोगग्रस्त खेतों में बिजाई न करें। बीज का सूखा उपचार 2 ग्राम थाइरम प्रति किलोग्राम बीजों की दर से करें।

पीला रतूआः इस रोग के कारण पत्तों पर पीले रंग के छोटे-छोटे धब्बे कतारों में बन जाते है। यह धब्बे डंठलों पर भी हो जाते हैं।

प्रबंधनः- रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें जैसे WH157, WH283, WH1124 आदि। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर 800 ग्राम जिनब या मैनकोजन नामक दवाई को 250 लिटर पानी में मिलाकर 10-15 दिन के अंतराल से दो-तीन छिड़काव करें।

पत्तियों की कांगियारीः यह रोग शुष्क क्षेत्रों में होता है। इस रोग के कारण पत्तों पर काली लंबी धारियां नसों के साथ-साथ हो जाती हैं जो बाद में फट जाती है और काला चूर्ण-सा बन जाता है।

प्रबंधनः- रोगी पौधों को नष्ट कर दें। रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें। 2 ग्राम वीटावैक्स या बाविस्टिन नामक दवाई 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचार करके ही बिजाई करें।

खुली कांगियारी या लुज स्मट रोगः इस रोग के कारण गेहूं की बालियां काले पाऊडर के रूप में हो जाती है। यह रोग सभी भागों व लगभग सभी किस्मों में पाया जाता है।

प्रबंधनः- इस बीमारी के लिए मई-जून के महीने में तेज धूप वाले दिन पहले बीज का पानी में चार घंटे भिगोए और उसके बाद पतली परत के रूप में पक्के फर्श पर सुखाएं। बीज का विटावैक्स या बाविस्टीन नामक दवाई 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से सुखा उपचार करे।

सरसों

तना गलनः लंबे आकार के भूरे जलसिक्त धब्बे तनों पर हो जाते है तथा इन धब्बों पर सफेद फफूंद लग जाती है। पौधे मुरझा जाते हैं तथा तनों पर या तनों के भीतर काले रंग के पिंड बन जाते हैं।

प्रबंधनः बिजाई से पहले बीज का 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करे। जहां पर तना गलन रोग का प्रकोप हर साल होता हो वहां बिजाई के 45 से 50 दिन तथा 65 से 70 दिन के बाद 0.1 प्रति-रु 39 यात की दर से बाविस्टिन नामक दवाई का 2 बार छिड़काव करें।

सफेद रतूआः पछेती फसल में यह रोग अधिक होता है। इस रोग से तने तथा पत्तियों पर सफेद अथवा पीले रंग के कील से प्रकट हो जाते है।

प्रबंधनः बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर 600 ग्राम मैनकोजब को 250-उचय300 लिटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर तीन से चार बार फसल पर छिड़काव करें।

जौ

खुली कांगियारी रोगः-ः इस रोग के कारण जौ की बालियां काले पाऊडर के रूप में हो जाती है।

प्रबंधनः- इस बीमारी के लिए मई-जून के महीने में तेज धूप वाले दिन पहले बीज का पानी में 4 घंटे भिगोए और उसके बाद पतली परत के रूप में पक्के फर्श पर सुखाएं। बीज का विटावैक्स या बाविस्टीन नामक दवाई 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से सुखा उपचार करे।

धारियों वाला रोगः-ः इस रोग के कारण पत्तों पर लंबी गहरी भूरी धारियां पड़ जाती हैं।

प्रबंधनः जहां यह बीमारी आती हो वहां लंबा फसल चक्र अपनाएं। खेत में सफाई रखें। रोग के लक्षण नजर आने पर 600 ग्राम डायथेन नामक दवाई का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें।

प्याज

पर्पल ब्लाच रोगः इस रोग के प्रकोप से फूलों की डंडी तथा पततियों पर जामुनी या गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते है जो बाद में बीज को हानि पहुंचाते है।

प्रबंधनः यह रोग फसल में दिखने पर 400-500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ओक्सीक्लोराड़ या ईन्डोफिल नामक दवाई को 200 से 250 लिटर पानी में मिला लें तथा किसी चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें।

आलू

पछेती अंगमारी या लेट ब्लाईट रोगः इस बीमारी के लक्षण सबसे पहले पत्तों पर काले-काले चकत्तों के रूप में दिखाई देते है जो बाद में पत्ते मर जाते है। प्रभावित पत्तों से बदबू आने लगती है। आलू के कंद भी इस रोग से प्रभावित होते हैं।

प्रबंधनः-इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर 600 से 800 ग्राम मैनकोजब नामक दवा के प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल से चार से पांच बार छिड़काव करें।

कपास

उखेड़ा और जड़ गलन रोगः खेड़ा रोग से पूर्ण पौधा या पौधे का कुछ भाग खत्म हो जाता है। अगर इनकी जड़ों को लंबाई की तरफ चीर कर देखे तो भूरे रंग की धारी नजर आती है। जड़ गलन रोग से पौधे की ऊपरी पत्तियां मुरझा जाती है। रोगी पौधों को उखाड़ कर देखा जाये तो उनकी जड़ें कुछ चिपचिपी सी गली हुई लगती हैं और छाल भी उतरने लगती है।

प्रबंधनः बीज का उपचार एमिसान (5 ग्राम), स्ट्रैप्टोसाईक्लिन (1 ग्राम), पानी (10 लिटर) का घोल बनाकर उसमें 5-6 किलोग्राम रोएंदार बीज (6-8 घंटे) या 6-8 किलोग्राम बगैर रोएदार बीज (2 घण्टे) तक उपचार करे। उसके बाद बीज का 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से सुखा उपचार करे। खड़ी फसल पर लक्षण दिखाई देने पर 0.2 प्रति- किलो बाविस्टीन का घोल बनाकर मोटे फैवारे का प्रयोग करके जड़ों में दें।

पत्ती मरोड़ रोगः इस रोग के कारण पत्तों की छोटी नसें मोटी हो जाती है। पत्तियां ऊपर की तरह मुड़ कर कप जैसी आकृति की हो जाती है। ब-सजय़वार रूक जाती है।

प्रबंधनः यह रोग सफेद मक्खी के कारण फैलता है। सफेद मक्खी का नियंत्रण करने के लिए 300 मिलीलीटर मैटासिस्टोक को 250 लिटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जहां पर यह रोग लगता है वहां भिण्डी की फसल न करें।

प्रीति वर्मा, विनोद कुमार मलिक और ममता खेपड
एचएयू हिसार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पश्चिमी यमुना नहर काछ्वा पुल के नजदीक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क 3.10 एकड़ में बनाया गया है तथा इस पर 2.40 करोड़ रुपए की लागत आई है।

मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत और सरलीकृत दावों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास' नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है।

अमृत सरोवर

जल संचयन की पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करने का प्रयास

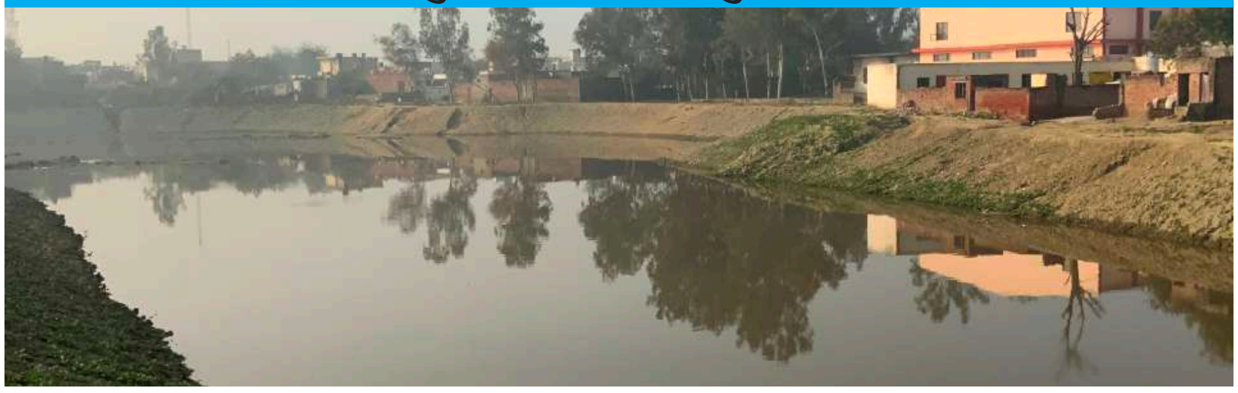

वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक की अवधि को अमृत काल का नाम दिया है। अमृत काल में हमारी खोई हुई विरासत को फिर से मजबूत करने के साथ ही गांवों में जल संचयन की हमारी पुरानी पद्धति जैसे जोहड़ व तालाब आदि को पुनर्जीवित व विकसित करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में 1650 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन लोगों से मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश में 2700 से अधिक अमृत सरोवरों को पुनर्जीवित व विकसित किया जा रहा है।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरुग्राम जिला में अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत गांव हरियाहेड़ा व दोहला में विकसित किए गए तालाबों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में अमृत सरोवर परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले तालाबों को आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है।

अमृत सरोवर परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे इन सरोवर की यूजर बॉडी का बनना अत्यंत आवश्यक है। इन अमृत सरोवर का जो लोग उपयोग करेंगे वो इसमें भागीदार अवश्य होने चाहिए।

उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यूजर बॉडीज बनाने के साथ ही इस बात पर भी मंथन करें कि इन बॉडीज को अमृत सरोवर की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। किसी भी अमृत सरोवर की प्लानिंग में ग्रामीणों के सुझाव भी जरूर लें और यदि ग्रामीणों को गांव में एक से अधिक अमृत सरोवर की आवश्यकता है तो इस पर भी विचार करें।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अमृत सरोवरों के निर्माण व जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया में रुटजोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गांव हरियाहेड़ा में अमृत सरोवर के निर्माण में सीएसआर पार्टनर हुंडई का सहयोग लिया गया है। वहीं गांव दोहला में निर्मित अमृत सरोवर को डी प्लान के तहत तैयार किया गया है।

घर बैठे मोबाइल से खेत की मोटर चालू-बंद

युवाओं को सिर्फ़ सरकारी नौकरी को फोकस करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपनी रूचि के अनुरूप कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सिरसा के रूपावास गांव के युवा सुनील ठोलिया है। बी.टेक उद्यमी सुनील ने अपने भाई की समस्या को हल करने 'मोबाइल मोटर स्टार्टर' प्रोडक्ट तैयार किया। जिससे उन्हें रोज शाम को मोटर चालू करने और सुबह बंद करने खेत में नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर बैठे ही मोबाइल से अपनी मोटर बंद कर देते हैं। इससे मोटर सड़ने व पानी की बर्बादी से बचत होती है। साथ ही अंधेरे में मोटर चलाने जाने से कई बार किसानों को सांप काटने जैसे घटनाएं घट जाती थी, उससे भी निजात मिली है। आज विभिन्न राज्यों के 23,500 किसान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके राहत महसूस कर रहे हैं। सुनील ने हाल ही में मोबाइल से सोलर पंप चलाने व खेत में तार काटने जैसे चोरी की घटनाओं को पता लगाने पर यंत्र भी तैयार किया है। उन्हें हरियाणा सरकार की स्टार्ट अप मुहिम के अंतर्गत 10 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा, जिससे वह अपने कारोबार का विस्तार करेंगे।

300 लोगों को मिल रहा काम

हिसार शहर के डाबड़ा चौक ओवरब्रिज के पास की राधा स्वामी कॉलोनी में अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले सुनील ने बताया कि हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेंटर से आर्थिक मदद और उचित निर्देश मिला। अब सलाना टर्न ओवर करीब 50 लाख हो चुका है। इनके समेत 11 लोग यहां काम करते हैं। इसके अलावा फील्ड में 300 कारीगर हैं, जो उपकरण किसान के मोटर में लगाने व मरम्मत का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर युवाओं को स्टार्ट-अप की ओर आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वह सराहनीय है। सरकार की ओर से समय-समय पर प्रशिक्षण और अन्य जानकारी भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मेलों में भाग लेने का मौका मिलता है, जिससे वे प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और नए ऑफर मिलते हैं।

मोबाइल मोटर स्टार्टर से मिला फ़ायदा

किसान दिनेश नरवाल बताते हैं कि मैं गत तीन सालों से मोबाइल मोटर स्टार्टर प्रयोग कर रहा हूं और इससे मेरा 20 हजार रुपए का डीजल बचा है। मध्यप्रदेश से संदीप गुलिया ने बताया कि पिछले दो साल से मोबाइल मोटर स्टार्टर उपयोग कर रहा हूं और मोटर जलने से बची हुई है। नेपाल के मिलन ने बताया कि केबिन टेक के काफ़ी प्रोडक्ट यहां लगे हैं। पहाड़ों में मोबाइल से मोटर चलाने से बहुत सुविधा हो रही है। नेपाल से केशव बिष्ट का कहना है कि इनके मोबाइल से चलने वाले स्टार्टर प्रोडक्ट नेपाल में बहुत उपयोगी है। ये मोबाइल से मोटर चलाने के इलावा मीटर को पूरी सुरक्षा भी देते हैं। भिवानी से इंद्र श्योराण ने कहा कि इनका प्रोडक्ट 2020 से चला रहा हूं अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सुमेर चंद ने कहा कि सुनील जी के प्रोडक्ट से घर के सभी उपकरण जलने से बचते हैं और मोबाइल स्टार्टर के प्रयोग से सांप से बचाव और बार-बार खेत आने-जाने के झंझट से मुक्ति मिल गई है।

छोटे ताल में अधिक मत्स्य उत्पादन

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में बढ़ोतरी

मछली पालन के व्यवसाय में तरक्की की अपार संभावनाएं हैं। किसान इस व्यवसाय को खेती के रूप में अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। ऐसी ही मिसाल नीलोखेड़ी कस्बे के छोटे से गांव बुटाना के प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह ने पेश की है, जिसने न केवल मछली पालन के क्षेत्र को अपनी आय का साधन बनाया है बल्कि इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करके सुल्तान सिंह आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत है।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह के मछली फार्म का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान सिंह ने पिछले 40 साल में कड़े परिश्रम व शोध करके मछली पालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने इजराइल की तकनीक को अपनाकर कम पानी में मछली का बेहतरीन उत्पादन किया है तथा नवीन पद्धति पर आधारित बीज भी तैयार किया है।

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई हैं। इसी के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 124 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है।

राज्य सरकार द्वारा सामान्य जाति के किसानों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के लोगों को भी मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ-साथ तालाब लीज पर लेने, मछली बीज इत्यादि के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार की इस योजना से जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे हैं, वहीं पंचायती तालाबों के पट्टे पर दिए जाने से पंचायतों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला है।

कुछ अलग करने का जज़्बा

किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि उनके परिवार के लोग शुरू से ही परंपरागत खेती करते थे, लेकिन मेरे अंदर परिवार से हटकर कुछ अलग करने का जज्बा था। इसलिए मैंने अपनी बीए की पढ़ाई के दौरान ही मछली पालन पर काम शुरू कर दिया था इसके बाद मैं केवीएफ के संपर्क में आया, जहां डॉ. मारकंडेय ने मछली बीज उत्पादन का प्रशिक्षण दिया और मैंने उत्तर भारत की पहली मछली बीज हैचरी का निर्माण किया और बीज बेचने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा राजस्थान एवं महाराष्ट्र में भी डैम को पट्टे पर लेकर काम शुरू किया हुआ है।

इस तकनीक में कम भूमि में अधिक मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने 1200 गज में इस सिस्टम को लगाया है जहां पर रिकॉर्ड 50 से 60 टन मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं, इस तकनीक से तैयार मछली का मार्केट में मूल्य भी अधिक मिलता है। वहीं इस तकनीक में 90 प्रतिशत पानी को रि-साइकिल किया जाता है। इस तकनीक को वह किसान आसानी से अपना सकते हैं जिनके पास भूमि कम है।

-संवाद ब्यूरो

जोखिम वाली श्रेणी में काम करने वाले ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना' बनाई है।

दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में मदद के लिए छोटे व्यापारियों के लिए 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' बनाई गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करेगी टोनी ब्लेयर फाउंडेशन

हरियाणा भवन, नई दिल्ली में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से शिष्टाचारपूर्वक मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने टोनी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर परस्पर सहयोग करने और नई संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा हुई। टोनी ब्लेयर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी संस्था टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसके लिए भी आयुष्मान भारत योजना तथा चिरायु हरियाणा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोल रही है, जिससे न केवल डॉक्टरों की कमी पूरी होगी बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन के सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में और विस्तार होगा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी।

आईटी के उपयोग से पारदर्शिता हुई सुनिश्चित

हरियाणा सरकार ने अपनी अनेक योजनाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है, जिसके चलते नागरिकों तक योजनाओं व सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है। सीएम ने टोनी ब्लेयर को बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों में आईटी का उपयोग करते हुए एक नया प्रयोग किया है। राज्य में रह रहे हर परिवार को एक इकाई मानते हुए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। इस एक दस्तावेज में परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, नौकरी, व्यवसाय, स्व रोजगार इत्यादि जानकारी दर्ज है। अब हर पात्र परिवार को पीपीपी के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ बिना किसी कार्यालय के चक्कर काटे बिना समयबद्ध तरीके से मिल रहा है।

महिलाओं के लिए चुनौती है पत्रकारिता: डा. सोनिया

'मेरे लिए यह गर्व की बात है कि आज मुझे प्रतिष्ठित एवं चर्चित महिला पत्रकारों से रू-ब-रू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकादमी द्वारा सम्मानित होने वाली ये महिला पत्रकार चंडीगढ़ तथा पंचकूला स्थित विभिन्न समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। मीडिया एवं पत्रकारिता के जटिल व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों के बारे में उनके विभिन्न अनुभव जहां हमें अपने समाज का आईना दिखाते हैं, वहीं आने वाले युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होंगे।'

उक्त विचार डॉ.सोनिया खुल्लर महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, चंडीगढ़ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा साहित्य अकादमी तथा हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा अकादमी परिसर में आयोजित महिला पत्रकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने महिला पत्रकार नोनिका सिंह, शायदा बानो, वंदन बत्रा, गीतांजलि गायत्री, शिमोना कपूर, मेघा कुमारी, लीली स्वर्ण, अर्चना सेठी, डॉ. बिंदु शर्मा, डॉ. मीनाक्षी वशिष्ठ को महिला पत्रकार सम्मान से सम्मानित भी किया।

महिला पत्रकार सम्मेलन में द ट्रिब्यून के लाइफ स्टाइल की इंचार्ज वरिष्ठ पत्रकार नोनिका सिंह ने अपने अनुभव सांझा करते हुए कहा कि महिला पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने व्यवसाय तथा पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना है। पत्रकारिता में लेखन की विशेष शैली का सर्वाधिक महत्व है जो आपकी एक अलग पहचान बनाती है। इसी प्रकार दैनिक ट्रिब्यून की समाचार संपादक डॉ. मीनाक्षी वशिष्ठ ने कहा कि पत्रकारिता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन धैर्य और समझ-बूझ से इसे आसान बनाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पधारी प्रो. बिंदु शर्मा ने कहा कि छात्राएं आजकल पत्रकारिता की अपेक्षा अध्यापन व्यवसाय को बेहतर मानती है। इसका कारण संभवतः पत्रकारिता में आने वाली चुनौतियां ही कही जा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार शिमोना कंवर ने कहा कि एक महिला पत्रकार ही एक नई स्टोरी एवं संवेदना में सामंजस्य बना सकती है।

द ट्रिब्यून की ब्यूरो चीफ गीतांजलि गायत्री ने अपने अनुभव सांझा करते हुए बताया कि किस तरह से उनकी स्टोरी से जरूरतमंद इंसानों को समाज की मदद मिलती है। इसलिए समाज में महिलाओं को अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखनी चाहिए। उर्दू पत्रकार लीली स्वर्ण ने अपने अनुभवों के साथ-साथ 'जस्ट अ वूमेन' कविता के माध्यम से नारी जीवन के विभिन्न पक्षों को चित्रित किया।

- संवाद ब्यूरो

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना

परिवार के लिए बहुत काम की हैं ये योजनाएं

मनोज प्रभाकर

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना विकट परिस्थिति में परिवार के लिए सुरक्षा चक्र का काम करती है। सामाजिक सुरक्षा योजना नागरिकों के बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। सड़क हादसों में होने वाली अकाल मौत और अंग-भंग होने पर आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ पेंशन योजना का लाभ भी शामिल है। खाता धारक को सालाना मामूली-सी प्रीमियम राशि देनी होती है, लेकिन मुश्किल समय में परिवार को मिलने वाली यह राशि बड़ी ही राहत प्रदान करती है।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके बैंक में खाते होते हैं और इन योजनाओं के लिए निर्धारित राशि सालाना प्रीमियम के तौर पर अदा करते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए अपने संबंधित बैंक में फॉर्म भरकर देना होता है। इसके बाद खाताधारक इस योजना से जुड़ा रहता है।

महज 20 रुपए में मिलता है योजना का लाभः

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ लेने के लिए महज 20 रुपए सालाना प्रीमियम देना होता है। 18 से 70 वर्ष तक इस योजना से जुड़ सकते हैं। हादसे में मृत्यु होने पर इस योजना से जुड़े परिवार को दो लाख रुपए बीमा कवर के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा किसी हादसे में एक हाथ या एक पैर या एक आंख खत्म होने पर अथवा दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख जाने पर एक लाख रूपए पीड़ित को मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजनों द्वारा या हाथ-पैर गंवाने वाले व्यक्ति द्वारा हादसा होने के 30 दिन के अंदर-अंदर अपने संबंधित बैंक में सूचना देनी जरूरी है।

दो लाख रूपए तक का बीमा कवरः

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सालाना 436 रूपए प्रीमियम खाता धारक को देना होता है। 18 से 50 वर्ष तक के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना में जुड़े व्यक्ति की सामान्य मौत पर भी परिजनों को दो लाख रूपए बीमें के रूप में मिलते हैं। इस योजना में भी संबंधित बैंक को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है।

आरडी की तरह है अटल पेंशन योजनाः

अटल पेंशन योजना आरडी की तरह है। 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना के लाभ ले सकते हैं। पांच तरह की पेंशन योजना है, इसमें शामिल हैं। एक हजार रुपए पेंशन लाभ के लिए उम्र के हिसाब से कम से कम 42 से 291 रुपए तक प्रति महीना, दो हजार रूपए पेंशन के लिए 84 से 582 रुपए प्रति महीना, तीन हजार रुपए पेंशन के लिए 126 से 873 रुपए प्रति महीना, चार हजार रुपए पेंशन के लिए 168 से 1164 रुपए प्रति महीना तथा पांच हजार रूपए पेंशन के लिए उम्र के हिसाब से 210 से 1414 रुपए प्रति महीना देना होता है।

मौत हो जाए तो ये मिलेगा लाभः

यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एक मुश्त लाभ संबंधित व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मिलता है। एक हजार रुपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को एक लाख 70 हजार रुपए, दो हजार पेंशन लाभ से जुड़े व्यक्ति के उत्तराधिकारी को तीन लाख 40 हजार रुपए, तीन हजार रुपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को पांच लाख 10 हजार रुपए, चार हजार रुपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को छह लाख 80 हजार रुपए तथा पांच हजार रुपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को आठ लाख 50 हजार रुपए मिलेंगे। असमय मृत्यु के दौरान इस योजना का लाभ लेने के लिए भी 30 दिन के अंदर संबंधित बैंक को सूचना देनी होती है।

अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' तैयार की गई है ताकि अंतिम व्यक्ति तक बीमा योजना का लाभ मिल सके।

'दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक' नई योजना शुरू की जा रही है जो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति या परिवार को सहायता प्रदान करेगी।

तनावमुक्त जीवन के लिए योग अनिवार्य

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान की जरूरतः रविशंकर

आर्ट आफॅ लिविंग के संस्थापक पद्म विभूषण गुरुदेव श्री रविशंकर ने तनाव को दूर करने के संबंध में कहा कि हमारे देश में बहुत साल पहले मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में साल 2022 में 400 डाक्टरों ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि इन सबके पीछे तनाव सबसे बड़ा कारण है, इसलिए ध्यान करने से तनाव कम होता है और मानसिक स्फूर्ति भी मिलती है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के क्षणों को ऐसे जियो कि ''हसंते रहो और हसांओ, न फंसो और न फंसाओ''। उन्हों कहा कि ध्यान करने से 100 से अधिक लाभ शरीर को प्राप्त होते हैं। इससे नशे और हिंसा से भी बचा जा सकता है क्योंकि ध्यान सबको जोड़ता है और अपनो से मिलाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करना है और सकारात्मकता से सुंदर समाज का निर्माण करना है और खुशियों को फैलाना है।

गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जो अपने आप में जीवन के मूल्यों का सार है और गीता का संदेश युद्ध के मैदान में दिया गया था, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए सार्थक है। हरियाणा का सौभाग्य है कि गीता का संदेश कुरूक्षेत्र के थानेसर की जमीन पर दिया गया। वर्तमान राज्य सरकार चरित्र निर्माण पर ध्यान दे रही है, इसी कड़ी में शिक्षा में नैतिकता और इतिहास की अच्छी बातों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक जिला व खण्ड स्तर पर गीता के संदेश व शिक्षा को पहुंचाने के लिए गीता जयंती मनाई जाती है। कुरुक्षेत्र में यह आयोजन 18 दिनों तक होता है ताकि जीवन मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष व्याख्यान ''हर घर ध्यान'' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गीता जंयती कार्यक्रम को उनकी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है जिसके तहत इंग्लैंड, कनाडा और मॉरीशस इत्यादि देशों में गीता जयंती को मनाया गया है। अगले माह ही आस्ट्रेलिया में गीता जयंती कार्यक्रम मनाया जाएगा।

ध्यान और शांति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम 'तेरा है, मेरा है', को छोड़कर देश और प्रदेश को एक परिवार के रूप में देखेंगे तो देश व प्रदेश आगे बढ़ेगा। तनाव से मुक्ति पाने के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप से ध्यान को अपने जीवन में धारण करने से तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा, योग व ध्यान से तनाव को समाप्त किया जा सकता है।

'कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन' का सार :

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने गीता के श्लोक कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन का व्याख्यान करते हुए कहा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। 'हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है' इन दो वाक्यों के बीच का फासला बहुत कम है परंतु करना और बनना से जीवन के तनाव को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने करना और बनना के बीच के अर्थ को समझाते हुए कहा कि जो हमें करना है उसकी चिंता नहीं की जाती और वह तनाव भी नहीं करता लेकिन जो हमें बनना है वो तनाव करता है क्योंकि हम हर पल यही सोचते रहते हैं कि मुझे फलां जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनना है, हम उसकी चिंता में तनावग्रस्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया वे साल 1980 में दिल्ली में आरएसएस में थे। तो वहां उन्हें करना और बनना के बीच का फर्क समझ आ गया था। उन्होंने सोच लिया था कि देश की सेवा करनी है। उसके बाद मुझे कभी भी तनाव नहीं हुआ क्योंकि मुझे क्या करना है यह पता चल गया था।

- संवाद ब्यूरो

महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए अहम कदम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सब मिलकर यह संकल्प लें कि देश व प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकेंगे तथा नारी का सम्मान बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। 'मातृ देवो भव', जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं। इसलिए नारी की रक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 154 महिलाओं को पुरस्कार व इनाम दिए गए।

उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब उन्होंने 10वीं पास कर आगे की पढ़ाई करने की ईच्छा व्यक्त की थी तो उनके पिताजी ने इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वे आगे पढ़ना चाहते हैं, उस दौर में मां ने उन्हें 300 रुपए दिए, जिससे उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मां का ही हाथ है, यदि मां ने वो पैसे न दिए होते तो शायद आज वे इस प्रकार भूमिका में खड़े न होते।

मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 56,434 है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया कि परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डाटा के अनुसार जिन परिवारों की आय एक लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाए, ताकि उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे स्वाभिमान से अपना जीवनयापन कर सकें।

पंचायतों में आरक्षणः

राज्य सरकार ने पंचायतों व नगर निकायों में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। ऐसा शायद ही किसी प्रदेश में हो। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार विशेष कदम उठा रही है। पुलिस में महिलाओं की संख्या जो वर्ष 2014 में 6 प्रतिशत थी, वह आज 10 प्रतिशत हो गई है और आगामी समय में इस संख्या को 15 प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य है।

महिला सुरक्षाः

महिला विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति वाहिनी व दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला थाने स्थापित किए हैं।

लिंगानुपात सुधारः

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। सरकार के साथ -साथ सामाजिक संस्थाओं ने अथक प्रयास किए जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में जो लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों का था, आज बढ़कर 923 हो गया है।

महिला शिक्षाः

राज्य सरकार ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 8 सालों में हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया गया है, ताकि लड़कियों को शिक्षा के लिए दूर दराज के क्षेत्र में न जाना पड़े । कुल 72 कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसमें से 31 कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं।

- संवाद ब्यूरो

'पीएम-कुसुम योजना' के तहत इस वर्ष 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है, इसे एक अप्रैल से लागू किया जा रहा है।

म्हारा देस म्हारी संस्कृति

कुरुक्षेत्र कला कीर्ति भवन में कलाकारों का धमाल

अलग-अलग वेशभूषा, बोली एवं लोक संस्कृति देश की न केवल विशेषता है, बल्कि खूबसूरती भी है। देश की एकता एवं अखण्डता के लिए जरूरी है कि सभी संस्कृतियों से रूबरू हुआ जाए और उनका सम्मान किया जाए। यह कार्य रंगमंच से जुड़े कलाकार बखूबी कर रहे हैं। लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां न केवल उनके प्रदेश की सभ्यता व संस्कृति का बखान करती है, अपितु उस प्रदेश के सामाजिक परिवेश का भी दर्शन कराती हैं।

कुरुक्षेत्र में स्थापित हरियाणा कला परिषद के कला कीर्ति भवन में नाट्य रंग उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2020 में कला कीर्ति भवन का नामकरण किया था, जिसकी चौथी वर्षगांठ पर नाट्य रंग उत्सव का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आगाज महाबीर गुड्डू ने शंखनाद से किया। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से आए कलाकारों ने दर्शकों के सामने अपने प्रदेश की संस्कृति के रंग बिखेरे। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति अंकित हरियाणवी के निर्देशन में पंकज, महेंद्र, सुभाष, रिचा चौहान, रमा भाटिया तथा वंशिका ने फाग नृत्य कर होली के त्यौहार की बधाई दी। इसके बाद पंजाबी लोक नाच सोसायटी के कलाकारों ने मोहित कुमार के निर्देशन में पंजाबी नृत्य झूमर प्रस्तुत किया। धीमे और लयबद्ध ढंग से कलाकारों ने झूमर नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। अगली प्रस्तुति राजस्थान के कच्ची घोड़ी नृत्य की रही। जोधपुर से आए हरि सिंह नागर और बाबू की टीम ने राजस्थानी संस्कृति को दिखाया। कालो कूद पड़यो रे मेला में जैसे गीतों पर दर्शक भी झूमते नजर आए। इसके बाद जश्नप्रीत और रवि कुनर ने अपनी गायकी से समां बांधा। मिर्जा जैसे गीतों की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। एक के बाद एक प्रस्तुति ने दर्शकों का खूब मन मोहा।

पंजाब के पुरुष तथा महिला कलाकारों द्वारा लोक संस्कृति की झलक दिखाता जिंदुआ विशेष तौर पर दर्शकों द्वारा सराहा गया। पंजाब की मुटियारों के साथ गबरु जवान जब जिंदुआ नृत्य के लिए मंच पर पहुंचे तो दर्शकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कार्यक्रम में जहां एक ओर पंजाबी गायकी से लोग आनंद विभोर हो रहे थे वहीं दूसरी ओर पंजाब के लोकनृत्यों ने भी खूब तालियां बटोरी।

- संवाद ब्यूरो

अंतिम सांस का कोई 'एक्सरे' नहीं होता

अंतिम सांस का कोई 'एक्सरे' नहीं होता। जी हां, यह एक अटल सत्य है कि प्रकृति अथवा नियति ही 'कैलेंडर' का आखिरी पन्ना लिखती है। फिल्म 'जाने भी दो यारो' और 'मिस्टर इंडिया' सरीखी बेहद चर्चित फिल्मों में अपनी बेहद लोकप्रिय एवं यादगार भूमिका निभने वाले सतीश कौशिक जिस अंदाज से इस नश्वर संसार से गए हैं वह भी दुखद, विचित्र एवं विस्मरणीय रहेगा।

एक दिन पहले होली के रंग और अगले ही दिन शोकगीतों की बारिश। बेहद अटपटा-सा था, सब कुछ। मगर यह सब तो हो चुका। सतीश जब मुंबई पहुंचे थे तो गुज़ारे के लिए अपने पिता के एक परिचित की कपड़ा मिल में भी काम करते रहे। अपने संघर्ष के दिनों की वह मज़े लेकर याद करते थे। श्याम बेनेगल की 'मंडी' में काम मिलने का किस्सा बहुत रस लेकर बताते थे। बेनेगल ने कहा था, सारी भूमिकाओं के लिए अभिनेता चुने जा चुके हैं फिर भी अपना फोटो छोड़ दें। 'हाज़िर-जवाब सतीश कौशिक ने कहा', फोटो तो नहीं है, ये एक्सरे रिपोर्ट देख लीजिए, मैं अंदर से बहुत अच्छा दिखता हूं। 'ठहाका लगाते हुए श्याम बेनेगल ने उन्हें काम दे दिया। अभिनय प्रतिभा, लेखक, सहायक निर्देशक, सह-निर्माता के काम भी करने लगे।'

हालांकि, पहली निर्देशित फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' की नाकामी से वह अवसाद में चले गए थे, पर उन्हें बाद में अच्छे निर्देशक के रूप में पहचाना गया। समग्रता में यह मानने में कोई हर्ज़ नहीं कि बतौर हास्य अभिनेता उनका सिक्का ज़्यादा चला। यद्यपि वह अक्सर कहा करते थे 'अभिनेता सिर्फ़ अभिनेता होते हैं।' उन्हें 'कॉमेडियन' तक सीमित रखना भी ज़्यादती है।

हरियाणा विशेष रूप से इस विशिष्ट एवं महान कलाकार की देन कभी नहीं चुका पाएगा। 'रूप की रानी चोरों का राजा' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले कौशिक ने 'हम आपके दिल में रहते हैं', 'हमारा दिल आपके पास है', 'बधाई हो बधाई', 'तेरे नाम' और 'मुझे कुछ कहना है' जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनके परिवार में पत्नी और बेटी हैं। कौशिक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र थे। हरियाणा में जन्में और दिल्ली के करोल बाग में पले-बढ़े कौशिक ने हमेशा अभिनेता बनने का सपना देखा था। उन्हें 'जाने भी दो यारो', 'राम लखन', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'मिस्टर इंडिया', 'दीवाना मस्ताना', 'हसीना मान जाएगी', 'छलांग', 'उड़ता पंजाब' जैसी फिल्मों में निभाए उनके किरदारों के लिए काफ़ी सराहना मिली। फिल्म 'मिस्टर इंडिया' में कौशिक के 'कैलेंडर' नाम रसोइये का किरदार निभाया था जो आज भी लोकप्रिय है। कौशिक ने 1983 में आई फिल्म 'जाने भी दो यारो', के संवाद और पंकज त्रिपाठी अभिनीत 'कागज' (2021) की कहानी भी खिली। कौशिक और अभिनेता गोविंदा की जोड़ी भी काफी मशहूर थी। 90 के दशक में 'स्वर्ग', 'साजन चले सुसराल', 'दीवाना मस्ताना', 'परदेसी बाबू', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'आंटी नंबर-1', और ' हसीना मान जाएगी ', जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए।

-डा. चंद्र त्रिखा

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com